International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 7 Issue 9, September- 2017,
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939|

पश्चिम बंगाल का राजंनैतिक इतिहास व इसका बदलता स्वरूप

(मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी/वाममोर्चा या लेफ़्ट फ्रंट से तृणमूल कांग्रेस तक) - एक अवलोकन

Dr Neeta Acharya, Political Analyst
Flat No. GG-803, Ashabari Complex,
Patuli, Kolkata (W.B)

पश्चिम बंगाल (भारतीय बंगाल) भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार हैं।इसकी राजधानी कोलकाता है। इस राज्य मे 22 ज़िले है। यहां की मुख्य भाषा बांग्ला है।

क्षेत्र के हिसाब से पश्चिम बंगाल भारत के छोटे राज्यों में गिना जाता है पर आबादी के हिसाब से यह सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में से है। यहां की राजधानी कोलकाता भारत का तीसरा सबसे बड़ा महानगर है। अन्य महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों में हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, खड़गपुर और हल्दिया हैं। पश्चिम बंगाल में 295 सीटों वाली एकल कक्ष विधान सभा है। राज्य से 58 सदस्य भारतीय संसद जाते हैं - 16 राज्य सभा और 42 लोक सभा। स्थानीय सरकार 22 प्रशासनिक जिलों पर आधारित है।

गोपाल कृष्ण गोखले ने कभी कहा था 'बंगाल जिसे आज सोचता है, पूरा देश उसे कल सोचता है'। राजनैतिक दृष्टि से जगरूक्ता के सम्बंध मे पश्चिम बंगाल काफी उन्नत रहा है। राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादी, भाकपा, ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय

दल जैसे तृणमूल कांग्रेस, एसयूसीआई, सीपीआईएमएल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, पीडीएस, जेडेएस, जेडीयू, आरएसपी आदि हैं।

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास के शुरुआती पन्ने बेहद अस्थिर राजनीति के रहे हैं । आज़ादी मिली और देश का विभाजन हुआ तो बंगाल का भी विभाजन हुआ। पश्चिम बंगाल का हिस्सा भारत में रह गया और पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान कहलाया । दोनों ही ओर को ख़ून ख़राबे के अलावा विस्थापन और शरणार्थियों की समस्याओं से रूबरू होना पड़ा। फिर 1971 में भारत के सक्रिय सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र देश होकर बांग्लादेश बना।

1967 से 1980 के बीच का समय पश्चिम बंगाल के लिए हिंसक नक्सलवादी आंदोलन, बिजली के गंभीर संकट, हड़तालों और चेचक के प्रकोप का समय रहा। इन संकटों के बीच राज्य में आर्थिक गतिविधियाँ थमी सी रही। इस बीच राज्य में राजनीतिक अस्थिरता भी चलती रही। आज़ादी के बाद से 1967 तक तो कांग्रेस का शासन रहा। कोई आठ महीनों के लिए बांग्ला कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड फ़्रंट ने सत्ता संभाली इसके बाद तीन महीने प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक गठबंधन ने राज किया फिर फ़रवरी 1968 से फ़रवरी 1969 तक एक साल राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। बमुश्किल एक साल (फ़रवरी 1969 से मार्च 1970 तक) बांग्ला कांग्रेस ने सत्ता संभाली फिर आगे के एक साल राष्ट्रपति शासन का रहा. अप्रैल 1971 से जून 1971 तक कांग्रेस ने राज्य में सत्ता संभाली लेकिन सरकार क़ायम न रह सकी और जून 1971 से मार्च 1972 तक फिर राष्ट्रपति शासन लगाना पडा ।

पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में स्थिरता का दौर

वर्ष 1972 के मार्च में, बांग्लादेश के निर्माण काल के दौरान इंदिरा गांधी के सहयोगी रहे सिद्धार्थ शंकर रे ने सत्ता संभाली जो आपातकाल के दौरान और उसके बाद चुनाव होने तक सत्ता में रहे । जून 1977 में जब आपातकाल के बाद देश में परिवर्तन की लहर चली तो पश्चिम बंगाल में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में वाममोर्चा या लेफ़्ट फ़्रंट ने सत्ता संभाली और ज्योति बसु राज्य के मुख्यमंत्री बने ।

वाममोर्चे की सरकार ने राज्य में भूमि सुधार जैसे असाधारण काम किए और आम लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की कोशिश की । वाममोर्चे के जनोन्मुख नीतियों का इतना सकारात्मक असर हुआ और राज्य में कांग्रेस की स्थिति लगातार इतनी कमज़ोर होती गई कि अगले 34 सालों तक यानी वर्ष 2011 तक राज्य में वामपंथियों को सत्ता से कोई हटा नहीं पाया । 1947 से 1977 तक जहाँ राज्य में सात मुख्यमंत्री बदले और तीन बार राष्ट्रपति शासन रहा, वहीं 1977 से 2011 तक वाममोर्चा के सिर्फ़ दो मुख्यमंत्रियों ने कामकाज संभाला। पहले ज्योति बसु 21 जून 1977 से छह नवंबर 2000 तक मुख्यमंत्री रहे फिर अपनी उम्र का हवाला देते हुए जब वे मुख्यमंत्री पद से हटे तो बुद्धदेब भट्टाचार्य ने कमान संभाली और 2011 के मई में विधानसभा चुनाव तक पद पर बने रहे । इस बीच केंद्र में 1996 में यूनाइटेड फ़्रंट की सरकार बनी तो ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसका वह अब तक अफ़सोस करती है, जैसा कि समय समय पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओ के वक्तव्य से ज्ञात होता है ।

इस बीच कांग्रेस के अनुभवी नेता प्रणब मुखर्जी का कांग्रेस में दबदबा क़ायम रहा लेकिन वे पश्चिम बंगाल में ऐसी ज़मीन तैयार नहीं कर पाए जहाँ खड़े होकर वे वाममोर्चे को चुनौती देते। प्रियरंजन दासमुंशी जैसे लोकप्रिय नेता भी हुए लेकिन उनका क़द कभी इतना बड़ा नहीं हो सका कि वे वामपंथियों के लिए कांग्रेस को चुनौती के रुप में खड़ा करते । अलबत्ता युवा कांग्रेस के ज़रिए राजनीति में आईं तेज़ तर्रार नेता ममता बैनर्जी ने अपनी ज़मीन ज़रुर तैयार की और उसका पर्याप्त विस्तार भी किया। परन्तु इस सब के बावजूद 34 सालों तक यानी वर्ष 2011 तक राज्य में वामपंथियों को सत्ता से कोई हटा नहीं पाया ।

वाममोर्चे की कमज़ोर पड़ती ज़मीन

जब आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरु हुआ उसके बाद से वामपंथी सरकार ने धीरे-धीरे अपने को बदलने का क्रम शुरु किया, वर्ष 2000 के दशक में बुद्धदेब भट्टाचार्य के नेतृत्व में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) की चर्चा शुरु हुई और टाटा जैसे उद्योगपति को आमंत्रित करके कार उद्योग लगाने को कहा गया। लेकिन यह बदलाव वाममोर्चे को भारी पड़ा और इस औद्योगिक विकास के विरोध में ममता बैनर्जी का सितारा बुलंद होता गया । पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई और फिर धीरे-धीरे अपनी पार्टी को कांग्रेस से बड़ा कर लिया ।

तृणमूल कांग्रेस का उदय

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (अंग्रेज़ी: *All India Trinamool Congress*, संक्षेप नाम: टीएमसी) भारत का प्रमुख राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में सक्रिय है। चुनाव आयोग द्वारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का स्वीकृत चुनाव चिह्न 'दो फूल' हैं। इस चुनाव

चिह्न में राष्ट्रीय ध्वज के सभी रंग हैं। पार्टी का राजनीतिक नारा है 'माँ, माटी और मनुष्य)। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिह्न फूल और घास मातृत्व या हमारे राष्ट्र के तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। माटी या मातृत्व यहां माता या 'माँ' को निर्दिष्ट करता है।

तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठ्न का गठन ममता बनर्जी ने किया उनका राजनितिक सफ़र कम उम्र में शुरू हुआ । वो कांग्रेस पार्टी मे एक युवा नेता की हैसियत से काफी सक्रिय रहती थीं लेकिन 1984 में केवल 29 साल की उम्र में जाधवपुर से लोक सभा का चुनाव जीत कर वो पार्टी की नज़रों में अचानक से उभर गई थीं। सिंगूर में टाटा नैनो कार परियोजना और नंदीग्राम में औद्योगीकरण के ख़िलाफ़ चले आन्दोलन के नेतृत्व के बाद उन्हें विपक्ष की एक दबंग नेता के रूप में देखा जाने लगा था।

इस आन्दोलन में राज्य के बुद्धीजीवी भी उनके साथ थे । उन्हीं में एक थे थिएटर जगत के माने जाने निर्देशक कौशिक सेन। वह बताते हैं कि उस समय ममता बनर्जी आम आदमी की आवाज़ बन गयी थीं। ममता बैंनर्जी ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया जो वामपंथियों पर बहुत भारी पड़ाकांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अकेले अपने बूते बंगाल में साढ़े तीन दशक तृणमूल वामपंथी राज का अंत कर दिया लंबे। पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई और फिर धीरे-धीरे अपनी पार्टी को कांग्रेस से बड़ा कर लिया । तृणमूल कांग्रेस' को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है । भारतीय निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है । ध्यांत्व्य हो कि भारत में बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था है, जिसके चलते वो कोई भी दल जिसको भारत के कम से कम चार राज्यों में मान्यता प्राप्त हो वह राष्ट्रीय दल बन जाता है ।

वाम सरकार बनाम तृणमूल कांग्रेस

भारत में स्वतंत्रता के बाद क्रांति की प्रयोगशाला के तौर पर पश्चिम बंगाल का नाम सर्वोपरि है। साठदशकों तक वाम दलों सत्तर के दशक में हिंसात्मक नक्सलवाद आन्दोलन के बाद वहां कई- के मोर्चे की सरकार का शासन रहा। पश्चिम बंगाल भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा की सफलता का सबसे बड़ा उदहारण था और जब कुछ साल पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के हाथों वाम मोर्चे को जबरदस्त शिकस्त मिली, तब प्रदेश में वाम दलों की प्रासंगिकता पर ही सवाल उठ खड़ा हुआथा। परन्तु किसी निष्कर्ष पर पहुचने से पहले ये आवश्यक है की पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों के उत्थान और पतन के कारणों का अवलोकन किया जाये |

कम्युनिस्ट आंदोलन में भाकपा की स्थापना तिथि को लेकर कुछ विवाद है। ख़ुद भाकपा का मानना है कि उसका गठन 25 दिसम्बर 1925 को कानपुर में हुई पार्टी कांग्रेस में हुआ था। लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जो 1964 में हुए पार्टीविभाजन के बाद बनी थी-, का मानना है कि पार्टी का गठन 1920 में हुआ था। माकपा के दावे के अनुसार भारत की इस सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट इंटरनैशनल की दूसरी कांग्रेस के तुरंत बाद हुआ था। बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि 1920 से ही पार्टी के गठन की प्रक्रिया चल रही थी और इस संबंध में कई समूह भी उभर कर सामने आये थे। लेकिन औपचारिक रूप से 1925 में ही पार्टी का गठन हुआ। इसके शुरुआती नेताओं में मानवेन्द्र नाथ राय, अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और शफ़ीक सिद्दीकी आदि प्रमुख थे।

ज्योति बसु उनके सबसे प्रभावी नेता रहे, वो ना केवल २३ वर्षो तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री रहे बल्कि उन्हे किसी राज्य का लगातार सबसे लम्बे समय तक मुख्यमन्त्री रहने का गौरव भी प्राप्त है राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका पार्टी के पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति की बैठकों तक में प्रभावी थी । उनके समय में भारतीय राजनीति व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी । कुछ

क्षेत्रिय नेताओं का राजनीति के क्षितज पर उदय हो रहा था । कुछ वाम दलों और क्षेत्रियों दलों का गठबंधन हो रहा था, ऐसे में ज्योति बसु प्रधानमंत्री पद के एक सर्वसम्मत दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए । उनके पास बंगाल में वाम दलों को एक साथ रखने का काफ़ी लंबा अनुभव था (यह गठबंधन 33 साल तक वहां सत्ता में बना हुआ था लेकिन अब यह कमज़ोर होने के संकेत दे रहा है) ऐसे में केंद्र की राजनीति में एक अस्थीर गठबंधन को स्थिर बनाए रखना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम था, जिसके लिए ज्योति बासु तैयार थे, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने इसे दूसरी तरह से लिया माकपा ने इस गठबंधन सरकार में शामिल न होने और उसे बाहर से समर्थन देने का फ़ैसला लिया| इससे ज्योति बसु प्रधानमंत्री नहीं बन पाए | बाद में उन्होंने पार्टी के इस फ़ैसले को 'ऐतिहासिक भूल' करार दिया | उन्होंने लगातार 23 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया | बसु की सरकार ने राज्य में कई उपलब्धियाँ दर्ज कीं जिनमें प्रमुख है|

- नक्सलबाड़ी आंदोलन से बंगाल में पैदा हुई अस्थीरता को राजनीतिक स्थीरता में बदलना|
- उनकी सरकार का एक और उल्लेखनीय काम है भूमि सुधार, जो दूसरे राज्यों के किसानों के लिए आज भी एक सपना है|
- ज्योति बसु की सरकार ने जमींदारों और सरकारी कब्ज़े वाली ज़मीनों का मालिक़ाना हक़ क़रीब 10 लाख भूमिहीन किसानों को दे दिया. इस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की ग़रीबी दूर करने में भी काफ़ी हद तक सफलता पाई|

सफलता के झंडे गाड़ने वाली बसु सरकार की कुछ कमियाँ भी रहीं. जैसे कि वह बार-बार हड़ताल करने वाली ट्रेड यूनियनों पर कोई लगाम नहीं लगा पाई, उद्योगों में जान नहीं फूंक पाई और विदेशी निवेश नहीं आकर्षित कर पाई | यह सरकार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों की तरह तकनीकी रूप से दक्ष लोगों का उपयोग कर राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भी नहीं

खड़ा कर पाई |

पार्टी का अंतर्विरोध व कार्यकर्ताओ का हिंसात्मक रवैया बना तृणमूल कांग्रेस के उदय का कारण

वामपंथी सरकार ने विदेशी निवेश के सैकड़ो समझौता पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन उनमें से कुछ को ही अमली जामा पहनाया जा सका क्योंकि मज़दूर संगठन इसके पक्ष में नहीं थे |

बंगाल में वाम मोर्चे के शासन के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समेत अन्य वाम दलों के कार्यकर्ता अपने विरोधियों से हिंसात्मक तरीके से निबटने के लिए प्रख्यात थे। नक्सल आन्दोलन के दौरान आम हो चले हड़ताल, बंद और हिंसात्मक प्रदर्शनों को ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना हथियार बनाया | वाम दलों के दशकों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने ऐसे वर्गों का साथ लिया जिनमें कुछ अतिवादी और माओवादी तत्व भी शामिल थे | तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री है एक ऐसी महिला है जिन्होंने ने बंगाल से 34 साल के मजबूत साम्यवादी सरकार को उखाड़ फेंका। जो दुनिया की सबसे पुरानी निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टी सरकारों में से थी | अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सार्वजनिक रैलियो को संबोधित करना और धरना करना ये ममता बैनर्जी की ताकत थी। सिंगूर और नंदीग्राम में जबरन ज़मीन हथियाने पर उन्होंने विरोध किया था जिससे पश्चिम बंगाल की जनता में वे काफी लोकप्रिय बन गई। सिंगूर में टाटा नैनो कार परियोजना और नंदीग्राम में औद्योगीकरण के ख़िलाफ़ चले आन्दोलन के नेतृत्व के बाद उन्हें विपक्ष की एक दबंग नेता के रूप में देखा जाने लगा था| 2011 में हुए विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की अगुआई वाली तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 184 सीटें जीत कर बहुमत हासिल किया। प. बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। भाजपा ने लगभग 18 फीसद वोट हासिल करते हुए दो सीटें-आसनसोल व दार्जिलिंग जीत लीं। इन चुनावों में सबसे ज्यादा

फायदा तृणमूल कांग्रेस को हुआ और उसकी सीटें 19 से बढ़ कर 34 तक पहुंच गईं। दूसरी ओर, वाममोर्चा 23 फीसद वोटों के साथ महज दो सीटों तक सिमट गया। सिंगुर और नंदीग्राम में किसानों के हक में जमीन अधिग्रहण विरोधी लड़ाई के जरिए गरीबों की मसीहा के तौर पर उभरीं ममता ने 2011 के विधानसभा चुनावों में वामपंथियों के लगभग साढ़े तीन दशक लंबे शासन का अंत कर अपनी मंजिल हासिल कर ही ली। अब उनके सामने उस सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है।

वर्तमान सरकार (तृणमूल कांग्रेस) सामने चुनोतियां

- माओवाद प्रभावित नंदीग्राम और सिंगुर जिन्होंने माकपा के खिलाफ ममता को वोट दिया था, अब वे भी ममता के 'परिवर्तन' से परेशान हैं।

- देश अभी विचारधारा की राजनीति के जिस द्वंद्व, टकराव और संक्रमण काल से गुजर रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को अगर एक कसौटी की तरह देखें तो यह अतिरंजना नहीं होगी। दरअसल, जिस तरह पिछले चार दशक से देश में पश्चिम बंगाल वाम राजनीति का गढ़ रहा है और हाल के वर्षों में दक्षिणपंथ की राजनीति का केंद्रीय सत्ता में उभार हुआ है, उसमें इसलिए भी राज्य के चुनाव को एक खास जगह मिली हुई है कि कुछ साल पहले सत्ता से बाहर होने के बाद एक बार फिर से वामदलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, यहां तक कि अपने धुर विरोधी कांग्रेस से समझौता करना भी उनके लिए कोई परेशानी का सबब नहीं बना।

- बंगाल हमेशा ही एकता के लिए प्रसिद्ध है. यहां पर सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते है. सारे त्योहार मिलकर मनाते भी है. लेकिन अभी बंगाल में धर्म की राजनीति तेज होने लगी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तो पहले से ही एक समुदाय की नीति पर चलने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा और संघ परिवार ने भी राम के नाम पर रामनवमी से यहां अपने पांव जमाने की जो कवायद शुरू कर दी है। जिसके कारण ममता बनर्जी और भाजपा के बीच टकराव तेज होने लगी है। चिंता की बात यह भी है कि राजनीतिक संग्राम ने बहुत जल्द सांप्रदायिक रूप ले लिया है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अपने समर्थन के प्रसार के लिए बड़े तौर पर अल्पसंख्यक वर्ग को अपने साथ लेकर चल रही है और उनके निशाने पर आने वालों में अधिकतर दूसरे वर्ग के लोग हैं। यही नहीं, जिस तरह से बांग्लादेश से आने वाले अप्रवासियों को तृणमूल ने अपने वोट बैंक में शामिल किया है, उससे प्रदेश के निवासियों में चिंता बढ़ी है और उनमे तृणमूल के प्रति रोष है |

- हाल ही में हुए शारदा चिट फंड घोटाले, नारद स्टिंग ऑपरेशन, देसी बम बनाने और बरामद होने की दर्जनों घटनाओं और तमाम अपराधों के प्रति ममता के रवैये से भी तृणमूल के प्रति एक वर्ग का असंतोष बढ़ा है।

किसी भी मुख्यमंत्री का यह दायित्व होता है कि वह अपने राज्य मे शासन व्यवस्था को मजबूत रखे, परन्तु **आज** बंगाल तथा बंगाल की मुख्यमंत्री दोनों चर्चा के केंद्र में हैं। बंगाल रक्तरंजित राजनीति, साम्प्रदायिक हिंसा तथा शाही इमाम द्वारा जारी फतवे के लिए चर्चा में है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने मोदी विरोध के हठ तथा भ्रष्ट नेताओं के बचाव के चलते लगातार सुर्ख़ियों में हैं।

अब अहम सवाल है आम आदमी से जुड़े मुद्दों का, जिससे देश के हर नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म, ज़ात, भाषा या भौगोलिक क्षेत्र का हो, को जूझना ही पड़ता है. आम आदमी से जुड़े सवालों में मुख्य हैं भ्रष्टाचार से मुक्ति और शासन प्रशासन में पारदर्शिता, सबके लिए शिक्षा और सामान अवसर, कृषि, महिलाओं का उत्थान, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि. पिछले दशक में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खुलासों के कारण बनी परिस्थितियों ने फिर से वही साम्प्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का पुराना अलाप छेड़ने को मजबूर किया. पिछले दो सालों में सड़-गल गयी भ्रष्ट, साम्प्रदायिक और भाई-भतीजावाद पर आधारित राजनीति के खिलाफ हुए जन संघर्ष को जनता ने बहुत ही करीब से देखा है |

राजनीतिक दलों को यदि आने वाले समय में भी प्रासंगिक बने रहना है तो उन्हें विचारधारा, पध्दति और आचरण, सभी स्तरों पर सुधार करना होगा। तीनों के स्तर पर स्पष्टता, समझ और प्रतिबध्दता की आवश्यकता है। इसे नेता से लेकर कार्यकर्ता स्तर तक सुनिश्चित करना पड़ेगा। जनाकांक्षा आगे सत्ताकांक्षा पीछे, यह सभी के सामने बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और यह सब व्यवहार के स्तर पर भी दिखाना होगा।

संदर्भ सूची :

१. *Dainik bhaskar dated 02/09/2016*

२. *"Directory of District, Sub division, Panchayat Samiti/ Block and Gram Panchayats in West Bengal,* मार्च *2008". West Bengal.* राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, भारत. *2008-03-19.* अभिगमन तिथि*: 2008-11-19.*

३. जनसत्ता ***Published on April 23, 2016*** *1*

४. टेलीग्राफ़, सम्पदाकिया: आशीष चक्रवर्ती, राजनीतिक संपादक

५. http://www.wbassembly.gov.in/ पश्चिम बंगाल की वेब साईट पर उपलब्ध आंकड़े

६. *इंडियन एक्सप्रेस.* 31 मई 2016. अभिगमन तिथि: 31 दिसम्बर 2016

७. हिंदुस्तान टाइम्स दिनांक अप्रैल ०४, २०१७

८. *"The rise of BJP in West Bengal | Latest News & Updates at Daily News & Analysis dna*. 2014-05-17. Retrieved 2017-01-05